वर्ष 24 | अंक 1 | सांचौर, गुरुवार, 1 जनवरी 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4 | UDYAM-RJ-19-0033346

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ 24 का मित्र

गौरवशाली वर्ष

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

बेमिसाल 24 साल

सम्माननीय पाठकों

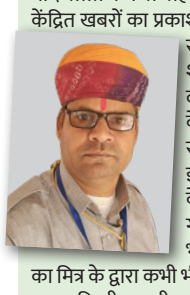

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र के प्रकाशन के 23 वर्ष पूर्ण हो गये है, आज से समाचार पत्र मारवाड़ का मित्र 24 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जनवरी 2003 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। इसके बाद सतत रूप से सहकारी आंदोलन पर आधारित और केंद्रित खबरों का प्रकाशन समाचार पत्र द्वारा किया जाता रहा है।

शुरूआती दौर में प्रकाशन के दौरान अनेक बाधाएं भी प्रबंधन के समक्ष उत्पन्न की गयीं। इन 23 सालों में मारवाड़ का मित्र के द्वारा ईमानदारी और विशुद्ध पत्रकारिता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। आज पाठक इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मारवाड़ का मित्र के द्वारा कभी भी और किसी भी तरह का अनैतिक दबाव किसी पर भी नहीं बनाया गया है। यह आप सभी का प्रेम, विश्वास और स्नेह ही था कि बीस वर्षों में पाक्षिक मारवाड़ का मित्र ने अपना एक अलग स्थान बना लिया है। मारवाड़ का मित्र ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन की सतत खोजी, निर्भीक, साफ-सुथरी खबरों का प्रकाशन कर यह साबित करने का प्रयास किया है कि सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की सहकारी संस्थाओं से जुड़े मुद्दो को किसान एवं इन संस्थाओं के हितार्थ प्रमुखता के साथ उठाया जाना चाहिये। मारवाड़ का मित्र के द्वारा सहकारी क्षेत्र पर संपादकीय का सतत प्रकाशन के साथ-साथ मारवाड़ का मित्र में देश भर के चुने हुए वरिष्ठ पत्रकारों, स्तंभकारों आदि के सारगर्भित और समसामयिक आलेखों का प्रकाशन किया जा रहा है।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन 23 वर्षों में मारवाड़ का मित्र सिर्फ एक अखबार ही नहीं वरन, सहकारी साख आंदोलन से जुड़े लोगों की अभिव्यक्ति और मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र बन गया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारे द्वारा सहकारी आंदोलन से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को वजनदारी के साथ उठाया जाये।

हमारा यह प्रयास भी रहा है कि मारवाड़ का मित्र की खबरें प्रमाणिकता से सराबोर रहें। बेकार, काल्पनिक, वैमनस्यतापूर्ण, पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों से इतर खबरों से परहेज किया जाये। हम अपना आँकलन खुद भी करते हैं और हमारी गलतियों से रूबरू कराने वालों का सदा ही मारवाड़ का मित्र प्रबंधन ने स्वागत किया है। दो दशक में मारवाड़ का मित्र की कामयाबी एवं अनवरत प्रकाशन का श्रेय निश्चित तौर पर सुधी पाठकगणों के समय-समय पर मिलने वाले मार्गदर्शन के साथ ही मारवाड़ का मित्र के कार्यालयीन सहयोगियों, प्रसार, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन अभिकर्ताओं, सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी इकाई पैक्स-लैम्पस सहित अनेक सहकार जनों एवं सहकार नेतृत्व कर्ताओं की कर्मठता एवं जीवटता को जाता है।

आज महंगाई के इस युग में समाचार पत्र का प्रकाशन वह भी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, बेहद दुष्कर कार्य ही है। फिर भी मारवाड़ का मित्र प्रबंधन के द्वारा गीता के ब्रह्म वाक्य कि "कर्म किये जा फल की चिंता न कर", को अपनाकर अपने पथ पर लगातार ही अग्रसर हुआ जा रहा है। हो सकता है कि कई बार मारवाड़ का मित्र की खबरों से किसी का दिल भी दुखा होगा पर हम यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि जब भी इस तरह की कोई बात हुई होगी और जिसका भी दिल दुखा होगा, उसने अगर आत्म मंथन किया होगा तो पाया होगा कि मारवाड़ का मित्र ने सदा ही सहकारी आंदोलन को समर्पित संस्थाओं के चिंतन एवं हित में ही खबरों का प्रकाशन किया है। मारवाड़ का मित्र वर्तमान में सहकारी आंदोलन को समर्पित एक अखबार है इसलिये हमारी कोशिश होती है कि इसमें सहकारी आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक संस्थाओं की खबरों को ही प्राथमिकता दी जाये। देश-प्रदेश की वे खबरें जो सहकारी आंदोलन की दृष्टि से पाठकों के लिये बहुत जरूरी हैं उनको ही अखबार में स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि सियासी दलों की देश-प्रदेश पर केंद्रित विज्ञप्तियों को अखबार में स्थान नहीं मिल पाता है। मारवाड़ का मित्र के कर्तव्यबोध की रगों में सुधि पाठकों के विश्वास का लहू ही कलम में रोशनाई के मानिंद बह रहा है। यही एक आधार है जिसके चलते मारवाड़ का मित्र अपना भाल ऊँचा रखने का साहस, शक्ति और धैर्य जुटा पाता है। हम आपसे वायदा करते हैं कि मारवाड़ का मित्र पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों, आदर्शों एवं मापदण्डों को अक्षुण्ण रखते हुए आपकी हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। आज मारवाड़ का मित्र की 24वीं वर्षगांठ पर कोटिः कोटिः बधाई, आप सभी का आभार, वंदन, अभिनंदन . . .।

।। जय सहकार ।।

.....प्रकाश वैष्णव
Publisher and Editor

एफआईजी पोर्टल का सर्वर के प्रति खरापन लगभग प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियां जानती है

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की ऋण वितरण प्रक्रिया अब एफआईजी पोर्टल के माध्यम से होगी क्रियान्वित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में गोपालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराने वाली राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण वितरण की समस्त प्रक्रिया अब फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे (एफआईजी) पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। असल में इस योजना को लेकर राज्य के कुछ जिलों में पिछले दो माह चली उथल-पुथल ने इस योजना का कायापलट करने के लिए विभाग को विवश कर दिया है। इसी के चलते अब विभाग ने पुरानी प्रणाली को बदलकर इस योजना को फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे (एफआईजी) पोर्टल पर लाने का ठान लिया है। इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग-प्रथम) प्रेम चन्द जाटव ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। जिसके मुताबिक जब तक राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का एफआईजी पोर्टल पर इन्टीग्रेशन नहीं हो जाता, तब तक के लिए वर्तमान में चल रही व्यवस्था को होल्ड किया जाएं। इसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के इन निर्देशों का क्रियान्वयन योजना अंतर्गत नवीन आवेदन के लिए किया जाने हेतु संयुक्त निदेशक राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) योजना भवन को पत्र लिखा है। जिसके मुताबिक इस योजना में नवीनीकरण के प्रकरण के लिए पूर्वानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

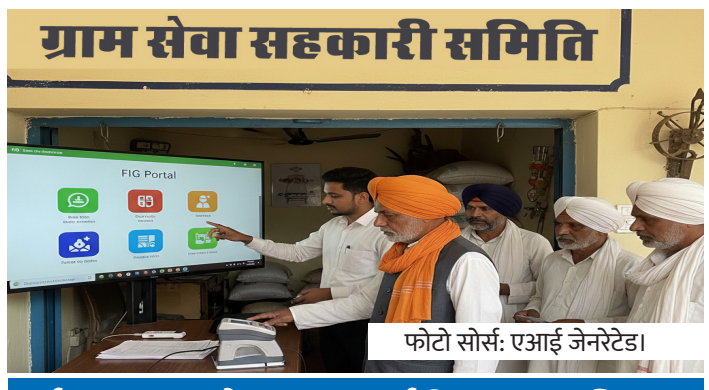

फोटो सोर्स: एआई जेनरेटेड।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाना उचित

राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पूर्व में वितरित ऋणों के रिन्युअल और नवीनीकरण के लिए वर्तमान व्यवस्थानुसार कार्य किया जाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग प्रथम) को पत्र लिखा है। प्रबंध निदेशक के अनुसार, इस योजना में वर्तमान व्यवस्था के तहत कार्य नहीं किए जाने पर ऋण राशि अवधिपार हो जाएगी और गोपालकों को भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही, सहकारी बैंकों को भी ब्याज अनुदान की हानि होगी। इसलिए नवीनीकरण व्यवस्था में शिथिलता दी जानी चाहिए।

सीसीबी एमडी निलंबित और कारण बताओं नोटिस

राज्य में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर पिछले सप्ताह बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक चर्चित रही। यहां, अनियमित ऋण वितरण की शिकायत पर सहकारिता विभाग पंजीयक ने जांच कमेटी गठित कर जांच करवाई, जिसके बाद सहकारिता विभाग द्वारा सीसीबी के प्रबंध निदेशक को निलंबित किया गया। साथ ही, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को भी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बाड़मेर जिले में अनियमितत ऋण वितरण की जानकारी होने के बाजवूद कार्यवाही नहीं करने के चलते कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

'जाल के पेड़' पर अटका एफआईजी पोर्टल

एफआईजी पोर्टल, यह नाम पिछले साल प्रदेशभर में किसानों के लिए 'चुनावी चस्को की तरह' खूब चर्चा का विषय रहा। इस पोर्टल का सर्वर के प्रति खरापन लगभग प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियां जानती है। क्योंकि इस पोर्टल के जरिए राजस्थान सरकार की ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना का क्रियावन्यन किया जाता है। इस योजना में भी किसानों को ऋण नवीनीकरण या यूं कहें नया-पुराना कराने के लिए भी एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सबब अधिकतर किसान इस पोर्टल की वजह से अवधिपार होकर रह गए है। यह पोर्टल हर वक्त सर्वर की समस्या वाले 'जाल के पेड़' पर लटका रहता है। इसे नीचे उतारने के लिए शीर्ष सहकारी बैंक ने खूब छलांग मारी, लेकिन यह पोर्टल सर्वर की समस्या के इस 'जाल के पेड़' से नीचे उतर ही नहीं पाया है।

"राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का क्रियान्वयन एफआईजी के माध्यम से किया जाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हैं, इस निर्णय से योजना में ऋण वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और प्रामाणिकता आएगी और पात्र गोपालकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही वसूली की लेखांकन से योजना की पारदर्शिता बरकरार रहेगी। पिछले दिनों इस योजना को लेकर ऋण वितरण में उजागर प्रकरण के बाद संपूर्ण राज्य में इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अनियमित ऋण वितरण की प्रभावी जांच करवाने के साथ-साथ दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग सरकार से करते है। **-सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता**

जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां की स्थिती बहुत दयनीय है, ऑडिट फीस देने तक का बना हुआ अभाव

सीसीबी प्रबंधन स्तर की मांग शीर्ष सहकारी बैंक तक पहुंची

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले की 80 फीसदी से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां की स्थिती बहुत दयनीय है। इनमें संस्थापन व्यय तक की राशि नहीं है और नहीं कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। यहां तक कि ऑडिट फीस देने का भी अभाव बना हुआ। इसी स्थिती को लेकर जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के ददरवाजे कई बार खटखटाने के बावजूद मांगों का निराकरण नहीं होने के चलते अंततः परेशान होकर जिला स्तर की समस्याओं के लिए पैक्स व्यवस्थापकों को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर कूच करना पड़ रहा है। दरअसल, जोधपुर सहकारी पैक्स कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक के नाम सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) श्रीमती सुमन जैन को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें 7 सूत्री मांगों के निराकरण की अपेक्षा की गई है। इनमें से अधिकतर मांग जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन स्तर की है। लेकिन यहां वर्षो से जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां को कमजोर बनाने की रीति और नीति का चलन चलाया जा रहा है।

RSCB सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) श्रीमती सुमन जैन को प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए

निर्देशों की हो रही अवहेलना

राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में समय पर ऋण चुकारा करने पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां को दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसको ग्राम सेवा सहकारी समितियां के बचत खाते में जमा करवाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। लेकिन इन निर्देशों की पालना जोधपुर सीसीबी में नहीं हो रही है। यूनियन की ओर बताया गया कि 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान ही जोधपुर जिले की अधिकतर ग्राम सेवा सहकारी समितियां का एकमात्र आय का स्रोत है। इसको भी सीसीबी द्वारा अवधिपार खाते में जमा किया जा रहा है।

सात सूत्री मांग की निराकरण की अपेक्षा

जोधपुर सहकारी पैक्स कर्मचारी यूनियन द्वारा जिन 7 सूत्री मांग के निराकरण की अपेक्षा की गई है। उनमें सीसीबी की शाखा में ग्राम सेवा सहकारी समितियां का ऋण और ब्याज खाता अलग-अलग रखने, 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि केवल सहकारी समिति के बचत खाते में जमा करने, 2017 तक नियुक्त सहायक व्यवस्थापकों को सहकारी समितियां का चार्ज देने, प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना का कमीशन समय पर देने की मांग के साथ किसानों की साख सीमा बढ़ाने के अधिकार भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्रमुखता से देने की मांग की शामिल है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 5 वर्ष के लिए 5 लाख तक का व्यवसायिक ऋण देने और साख सीमा का प्रत्येक समितिवार 10 प्रतिशत के आधार पर नवीनीकरण करवाने की मांग भी रखी गई। साथ ही, 50 हजार से अधिक के ऋणों की बढ़ाने का अधिकार व्यवस्थापक को देने की भी मांग उठाई गई है।

नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

जागनाथ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बागरा

पूर्णत: कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

आदाराम लुकडा
अध्यक्ष

जालमसिंह सिंघल
उपाध्यक्ष

जितेन्द्र कुमार
स. व्यवस्थापक

किसानों से अपील अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। पशुपालक, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

राज्य सहकारिता सेवा के पांच अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में एपीओ चल रहें राज्य सहकारिता सेवा के पांच अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। इसके लिए सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से आदेश जारी किया गया। जिसके अनुसार, संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी रायसिंह मोजावत को A.R.O जोधपुर एवं संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी शुद्धोधन उज्ज्वल को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर लगाया गया है। साथ ही, सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी रूप सिंह चारण को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बालोतरा, श्रीमती सुलोचना मेहरा सहायक रजिस्ट्रार (मोनीटरिंग) टी0ए0 सैल प्रधान कार्यालय जयपुर एवं पीथदान चारण को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डीडवाना-कुचामन लगाया गया है। हालांकि यह तबादला सूची जारी होने के बाद प्रदेश की अनेक केंद्रीय सहकारी बैंकों को योग्य एवं कुशल प्रबंध निदेशक का बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा जोधपुर संभाग में भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां का पद अतिरिक्त कार्यभार के सहारे पिछले दो माह से चल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सहकारिता विभाग की तबादला सूचियां तैयार होने से पूर्व ही विधायकों की अनुशंसा सहकारिता मंत्री तक पहुंचाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या नाबार्ड एवं आरबीआई के 'फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया' के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति हो पाती है? या फिर विधायकों की अनुशंसा को तवज्जो देकर फिर पुराने ढर्रे से केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद की कमान अयोग्य अधिकारियों को थमा दी जाएगी?

तबादला सूचियां तैयार होने से पूर्व ही विधायकों की अनुशंसा सहकारिता मंत्री तक पहुंचाई जा रही

विधानसभा में सहकारिता विभाग ने प्रस्तुत किया जवाब : व्यवस्थापकों के 4017 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समितियों से मांगी जा चुकी अभ्यर्थना

राज्य की 4017 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान में करीब 4017 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में व्यवस्थापक के पद रिक्त पड़े है। इन पदों पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती करवाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियां से रिक्त पदों की अभ्यर्थना मांगी गई है। दरअसल विधानसभा के चतुर्थ सत्र में बायतु विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियां में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को लेकर तारांकित प्रश्न किया इसका सहकारिता विभाग द्वारा पांच दिन पूर्व जबाव प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों की सूचना अपेक्स बैंक के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त कर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए भर्ती करवाने की तैयारी हैं, इसके लिए समितियों की अभ्यर्थना हेतु केंद्रीय सहकारी बैंकों को लिखा जा चुका है। जबकि विभाग ने सदन में लिखित जवाब पेश कर बताया कि जिन सहकारी समितियों में नियमित व्यवस्थापक पदस्थापित नहीं है, उन समितियों में अतिरिक्त कार्यभार या कार्य का दायित्व समिति के अन्य कार्मिक को दिया जाता है।

व्यवस्थापकों के 4017 पद रिक्त

विधायक के सवाल पर विभाग ने अपना लिखित प्रतिउत्तर दिया है कि अपेक्स बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 4017 पद रिक्त पड़े है। साथ ही, विभाग के मुताबिक पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवानियम 2022 में व्यवस्थापकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराये जाने का प्रावधान है, यह भर्ती प्रक्रिया सहकारी समितियों से अभ्यर्थना प्राप्त होने पर सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

स्क्रीनिंग पर न्यायालय की रोक

विधायक के सवाल पर विभाग ने स्पष्ट किया है व्यवस्थापक सेवानियम 2022 के तहत एक बारीय स्क्रीनिंग का प्रावधान है। जबकि, उच्च न्यायालय द्वारा दो प्रकरणों में स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई थी, इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय भी ली गई। जिसके अनुसार, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पर संपूर्ण राज्य में रोक लगाई है। इस कारण स्क्रीनिंग किया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा बीमा कवरेज

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने का जो फैसला लिया है, वह ढांचागत क्षेत्र में आर्थिक विकास के पक्ष में उठाया गया सुधारात्मक कदम है. इससे लोगों के बीच बीमा के प्रति अनुकूल धारणा बनेगी, इस क्षेत्र में पूंजी के साथ वैश्विक विशेषज्ञता भी आयेगी और बीमा कंपनियों की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ेंगे. अलबत्ता इस फैसले से विनियमन, घरेलू स्वामित्व और एलआइसी पर पड़ने वाले असर से जुड़े कुछ प्रासंगिक सवाल भी हैं, जिन पर सतर्कतापूर्वक विचार करने की जरूरत है. अगर समग्र रूप से प्रीमियम के स्थानीय निवेश और नियामक निगरानी से जुड़ी सहायक सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया गया, तो इसका प्रभाव वित्तीय समावेशन, क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक विकास के रूप में सकारात्मक होने की संभावना है. इस साल के बजट में ही बीमा क्षेत्र में एफडीआइ को 74 फीसदी से बढ़ा कर 100 फीसदी करने की घोषणा की गयी थी. हालांकि बढ़ायी गयी एफडीआइ सीमा का लाभ उन विदेशी बीमा कंपनियों को ही मिलेगा, जो पूरी प्रीमियम राशि का निवेश भारत में करेंगी. सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वित्तीय क्षेत्र में किये गये व्यापक सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बीमा के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाना, बीमा प्रक्रिया को सहज करना, इन्श्योरेंस एक्ट, एलआइसी एक्ट और आइआरडीएआइ एक्ट का आधुनिकीकरण है. इसका उद्देश्य देश की बड़ी आबादी के लिए किफायती लागत पर बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना है. बीमा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया देश में निरंतर चलती रही है. इसके तहत एफडीआइ की सीमा पहले 26 फीसदी से बढ़ा कर 49 प्रतिशत, फिर 74 फीसदी की गयी और अब 100 फीसदी की गयी है. इस क्षेत्र में हुए सुधार के कारण बीमा कंपनियों की संख्या कुछ सरकारी कंपनियों से बढ़ कर अब करीब 60 हो गयी है. गौरतलब है कि कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआइ की अनुमति दे रखी है.इस लिहाज से भारत भी अब इस क्षेत्र में वैश्विक मानक अपनाने जा रहा है. इसका तात्कालिक प्रभाव यह पड़ेगा कि बाजार में बीमा राशि की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बीमा कराने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ेगी, पेंशन और एन्युटि जैसे दीर्घावधि बीमा उत्पादों का चलन बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी में फंड निवेश बढ़ेगा. भारत जैसे देश में, जहां पूंजी आसानी से उपलब्ध नहीं है, सरकार द्वारा उठाये गये कदम से बीमाकर्ता ढांचागत और स्वास्थ्यगत क्षेत्र में बीमा का बड़ा जोखिम उठा सकेंगे. इससे व्यापक आर्थिक सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा और सरकारों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी कम होगा. जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, तो खासकर स्वास्थ्य और सामान्य बीमा के क्षेत्र में उन्हें प्रोडक्ट डिजाइन, लागत और सेवा की गुणवत्ता के मोर्चे पर बेहतर बीमा कंपनियों के विकल्प मिलेंगे. प्रतिद्वंद्विता बढ़ने से कंपनियां दावा निपटान की प्रक्रिया, डिजिटल इंटरफेस और शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार लाती हैं. इससे देश में बीमा कंपनियों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा और 2047 तक सभी नागरिकों के बीमित होने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा. सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में देश चूंकि वैश्विक औसत से बहुत पीछे है, लिहाजा नीति निर्माताओं को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में एफडीआइ की सीमा बढ़ाने से बीमा से दूर रहने वाले परिवारों और एमएसएमइ क्षेत्र को इसके दायरे में लाया जा सकेगा. बीमा क्षेत्र के घरेलू नेटवर्क को अतिरिक्त विदेशी पूंजी का साथ मिलेगा, तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों, वित्तीय कंपनियों तथा कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से बीमा कवरेज बढ़ाया जा सकेगा. चूंकि विदेशी बीमा कंपनियां अपने साथ आधुनिक बीमा प्रोडक्ट्स और तकनीक भी लायेंगी, ऐसे में, समय के साथ गिग वर्कर्स और छोटे कारोबारी इसके दायरे में आयेंगे तथा जलवायु संबंधित जोखिमों के लिए भी बीमा उत्पाद उपलब्ध होंगे. बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआइ की एक प्रमुख शर्त यह है कि पूरी प्रीमियम राशि का निवेश भारत में करना होगा.

जालोर जिले में सहकारी आंदोलन के स्वर्णिम 60 साल हुए पूर्ण : सहकारी आंदोलन ने बदली खेती की तस्वीर

किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने में कार्यशील सहकारी समितियां

> **सहकारी आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने एवं जन-जन में पिरोने के लिए राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी धनसिंह देवल, सहायक अधिशासी अधिकारी छतरसिंह राठौड़, आर.के.शर्मा, मंगलाराम विश्नोई तथा व्यवस्थापक सरदारसिंह राव, पहाड़सिंह सोलंकी, जैसाराम सैन, उदयसिंह देवड़ा, आदाराम लुकड़ा, बाबूसिंह राजावत, ऊके खॉ खोखर, प्रागाराम मेघवाल जैसे सहकारी साख संरचना जुड़े लोगों के योगदान का भुलाया नहीं जा सकता है ।**

आज जिले में सहकारी आंदोलन के स्वर्णिम 60 साल पूर्ण हुए है, करीब 1965 में इस सहकारी आंदोलन की नींव जिले में रखी गई थी । वर्तमान में सहकारी आंदोलन ने खेत, खलिहान, पशुपालन और ग्रामीण पृष्ठभूमि की तस्वीर और किसानों, गोपालकों एवं हनुरमंदों की तकदीर भी बदली है । हजारों युवाओं को रोजगार के साथ किसानों की भागीदारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए सहकारी आंदोलन में सुनिश्चित कर, हजारों किसानों और युवाओं को खुशहाली प्रदान की है । जिले में सहकारी आंदोलन की अनेक संस्थाएं जिला स्तर पर कार्यशील हैं और गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां का जाल बिछा हुआ है । सहकारी आंदोलन में अग्रणी रहे लोग अब सहकारी आंदोलन के उभरते स्तर से हर्षित है । वयोवृद्ध सेवानिवृत्त सहकारिता सेवा के कई अधिकारी बताते है कि उस समय किसान और मजदूर वर्ग गरीबी में जकड़ा हुआ था । किसान अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। पैसे की कमी से किसान सूदखोर के चंगुल में फंसकर कर्जदार हो रहा थे, साहुकार प्रथा चहुँओर निरंतर बढ़ रही थी । कर्ज न उतार पाने से किसान खेती विहीन होते जा रहे थे। ऐसे में सहकारी आंदोलन कारगर हथियार और किसानों की नई उम्मीद बनकर सामने आया। इस आंदोलन की नींव किसानों को नकद ऋण, खाद, बीज देने के लिए गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित कर, रखी गई इससे न केवल बेरोजगार युवकों को नौकरियां और किसानों को सुविधाएं मिलीं, बल्कि सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की इन ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने साहुकार प्रथा का भी दमन किया गया । असल में, सहकारी आंदोलन की जड़े जिले में जमाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की रियायती दर पर नकद ऋण योजना अहम साबित हुई । किसानों ने साहुकारों की उच्ची दरों वाले ऋण को छोड़कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण लेना प्रारम्भ किया । वही सहकारी आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने एवं जन-जन में पिरोने के लिए राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी धनसिंह देवल, सहायक अधिशासी अधिकारी छतरसिंह राठौड़, आर.के. शर्मा, मंगलाराम विश्नोई तथा व्यवस्थापक सरदारसिंह राव, पहाड़सिंह सोलंकी, जैसाराम सैन, उदयसिंह देवड़ा, आदाराम लुकड़ा, बाबूसिंह राजावत, ऊके खॉ खोखर, प्रागाराम मेघवाल जैसे साख संरचना जुड़े लोगों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता है । इन्होने गांव-गांव घूम जिले में सहकारी आंदोलन की अलख को जगाया और सहकारी आंदोलन का महत्व बताकर किसानों और ग्रामीण लोगों को जागरूक कर, सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की सबसे छोटी इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति से जोड़ा । इनके कर्तव्यनिष्ठ, कार्यप्रणाली, सहयोग एवं सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का निस्वार्थ जज्बा, आज जिले में सहकारी आंदोलन के पहाड़ जैसे रूप में देखा जा सकता है । बढ़ती आयु की परवाह किए बिना धनसिंह देवल एवं छतरसिंह राठौड़ सहकारिता के चिंतक थे। इनकी बदौलत आज जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां करोड़ों का व्यवसाय कर रही हैं और इन समितियां से जुड़ा प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है । जिले में करीब 1.50 लाख ऋणी किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत करीब 200 ग्राम सेवा सहकारी समितियां 805 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण मुहैया करा रही है । इसमें भी खरीफ सीजन में 379 करोड़ एवं रबी सीजन में 426 करोड़ का ऋण बांटा जाता है । इसके अलावा, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, पीडीएस, मिनी सहकारी बैंक, कॉमन सर्विस सेन्टर, खाद-बीज एवं कीटनाशक वितरण के अलावा किसानों को रियायती दर पर कस्टम हायरिंग सेन्टर के जरिए कृषि यंत्र मुहैया कराये जा रहें हैं । जिले में सहकारी आंदोलन का प्रारम्भ नकद ऋण योजना के साथ हुआ । इस ही मूल व्यवसाय की संरचना पर कायम रहकर, पैक्स कार्मिकों ने नरसाणा, बावतरा, डूंगरी, भूति, सैलड़ी, दूठवा, टांपी, सुराणा, चान्दुर ग्राम सेवा सहकारी समिति को मजबूत बनाया है । इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत सीसीबी की एक शाखा की सहकारी समितियां द्वारा सालभर में जितना ऋण वितरित किया जाता है, उतना ऋण केवल इस जिले की एक सहकारी समिति वितरित कर देती है । वर्तमान में किसानों की ऋण आवश्यकताओं को भली भांति समझकर इन समितियां ने किसानों को ब्याज मुक्त योजना से लाभान्वित करने का कार्य बखूबी किया है । इनमें नरसाणा पैक्स द्वारा सालाना 11 करोड़ का फसली सहकारी ऋण बांटा जाता है । इसी तरह बावतरा पैक्स द्वारा 10 करोड़, डूंगरी पैक्स द्वारा 10 करोड़, सैलड़ी पैक्स द्वारा 9 करोड़, भूति पैक्स द्वारा 8 करोड़, सुराणा पैक्स द्वारा 8 करोड़, टांपी पैक्स द्वारा 7 करोड़, चान्दुर पैक्स द्वारा भी 7 करोड़ का ऋण बांटा जाता है ।

व्यवसाय विविधीकरण से टॉप बनी यह समितियां

वर्तमान युग पर ध्यान केंद्रित कर जिले की सियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने व्यवसाय विविधीकरण को अपनाकर जिले में शिखर पर पहुंची है । इस समिति में मोबाइल वैन, लॉकर सुविधा के साथ एक ग्रामीण व्यावसायिक बैंक की तरह मिनी सहकारी बैंक का संचालन किया जा रहा है । इसी तरह, उम्मेदाबाद भी व्यवसाय विविधीकरण की दृष्टि से जिले की टॉप समितियां में शामिल है । यहां, पैक्स के दैनिक कार्य के अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र , ड्रोन के जरिए कीटनाशक एवं दवाईयों का छिड़काव करने, कस्टम हायरिंग सेन्टर चलाने का कार्य भी किया जा रहा है ।

पैक्स का कायाकल्प, अब बहुउद्देशीय बनकर बदलेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) अब केवल कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की 'सहकार से समृद्धि' पहल के तहत, पैक्स को आर्थिक रूप से सशक्त और बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो चुका है। इस बदलाव का मुख्य आधार 'आदर्श उपविधियां' हैं, जो पैक्स को नए व्यापारिक अवसर प्रदान करेंगी। अब तक पैक्स का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से किसानों को अल्पकालिक ऋण और खाद-बीज उपलब्ध कराने तक ही सीमित था। सीमित आय के कारण कई समितियां आर्थिक संकट से जूझ रही थीं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर 'आदर्श उपविधियां तैयार की हैं। इन नई उपविधियों को अपनाने के बाद, पैक्स अब 25 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकेंगी। जिससे एक ही छत के नीचे अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा । वही पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने का सीधा लाभ यह होगा कि अब ये समितियां डेरी, मत्स्य पालन, गोदाम प्रबंधन, और खाद्यान्न खरीद जैसे पारंपरिक कार्यों के अलावा आधुनिक सेवाएं भी दे सकेंगी। सहकारिता विशेषज्ञों का मानना है कि पैक्स के बहुउद्देशीय होने से उनकी आय में भारी वृद्धि होगी। जब एक ही छत के नीचे किसानों को खेती की जरूरतों के साथ-साथ बैंकिंग, दवाइयां और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। यह कदम न केवल पैक्स की बैलेंस शीट को सुधारेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर हैं। सहकारिता मंत्रालय की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि देश की लगभग 1 लाख पैक्स जीवंत आर्थिक इकाइयों के रूप में कार्य करें। आदर्श उपविधियों का अंगीकार करना सहकारिता आंदोलन के इतिहास में एक 'गेम चेंजर' साबित होगा। 'सहकार से समृद्धि' का सपना तभी साकार होगा जब सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली ये समितियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।

(यह लेख सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर का है ।)

नई व्यवस्था के तहत पैक्स अब

- कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर सकेंगी।
- पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकेंगी।
- जन औषधि केंद्र संचालित कर सकेंगी।
- बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के रूप में वित्तीय सेवाएं दे सकेंगी।
- एफपीओ का गठन कर सकेंगी।

फोटो सोर्स: एआई जेनरेटेड।

नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

दी. बाड़मेर सेन्ट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बाड़मेर

एक सब के लिए सब एक के लिए

प्रधान कार्यालय : महावीर नगर, बाड़मेर फोन : +91-02982-220461, 220345

फैक्स : +91-02982-220461 Email- DCCB.BARMER@RAJASTHAN.GOV.IN

बैंक की प्रमुख योजनाएं

- राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण
- व्यापारिक फर्म की आकस्मिक आवश्यकता हेतु सीसी लिमिट्स सुविधा
- ग्राहकों की जमाएं डिपोजिट इंश्योरेन्स गारंटी कॉरपोरेशन से बीमित व सुरक्षित।
- दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण योजना।
- आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण (मोर्गेज) योजना, शिक्षा ऋण, सहकार ग्राम आवास योजना
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठाएं। जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर

प्रबंध निदेशक | **प्रशासक बैंक**

बैंक सेवाओं तथा ऋण सुविधाओं की विस्तृत जानकारी हेतु बैंक की निकटतम शाखा में सम्पर्क करें।

24वें राज्य स्तरीय 'को-ऑप स्पोर्ट्स 2025' का हुआ समापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य के बाड़मेर जिले में स्पेक्ट्रम द्वारा इस बार तीन दिवसीय 'राज्य स्तरीय को-ऑप स्पोर्ट्स' का आयोजन किया गया । इसका समापन रविवार को बाड़मेर स्थित भगवान महावीर टाउन हॉल में किया गया । समापन समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह लूणसिंह झाला, विशिष्ट अतिथियों के तौर पर जोधपुर सीसीबी प्रबंध निदेशक अनिल बिश्नोई, पाली सीसीबी प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला, एआईसी स्टेट मैनेजर हरगोविंद मान एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली जितेंद्र कुमार ने भाग लिया । इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष एवं सीसीबी प्रबंध निदेशक हरीराम पूनिया द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया । वही इस खेलकूद प्रतियोगिता में सहकारी बैंकों के कर्मियों की खेल भावना, अनुशासन और सहयोग की भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। अंत में प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार व पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा, जोधपुर सीसी स्पेक्ट्रम अध्यक्ष एस.एल. स्वामी ने बताया कि स्पेक्ट्रम की आमसभा और नवीन कार्यकारिणी का भी किया गया । इसमें गत आमसभा की कार्यवाही का अनुमोदन, वार्षिक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । साथ ही, नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया । जिसमें अध्यक्ष के तौर पर सुनीता राजपाल, महासचिव के तौर पर प्रशांत कुमार, कोषाध्यक्ष के तौर पर डॉ. शिवशरण गुर्जर को निर्वाचित किया गया ।

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में दिखा जोश

हाई स्कूल ग्राउंड, बाड़मेर क्लब एवं पुलिस लाइन में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन ट्रैक एवं फील्ड इवेंट्स में 100 मीटर व 400 मीटर रिले दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिताओं में महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दूसरे दिन कैरम, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल व बैडमिंटन के लीग मैच संपन्न हुए। प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस हाई स्कूल ग्राउंड से बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने भाग लेकर खेल भावना और आपसी समन्वय का उत्कृष्ट परिचय दिया।

इस साल सहकारी गलियारों में रही काफी हलचल, सुर्खियां में रहा पोस्टर और एससी कांड, एफआईजी पोर्टल सर्वर डाउन सुधार के प्रयास भी आधे-अधूरे, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण वितरण से साख पर दाग

आयोजनों, समीक्षाओं, पैक्स कंप्यूटराईजेशन... और कर्ज माफी की बकाया ब्याज राशि को लेकर गुहार लगाने में बीता साल

वर्ष 2025 देश सहित प्रदेश में अंतराराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया। इस वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लेकर सहकारिता विभाग के गलियारों में 'सहकार से समृद्धि' और 'अंतराराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' का खूब शोरगुल रहा और भजनलाल सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति के मामलो में सहकारिता मंत्री का रवैया इस साल दबा हुआ नजर आया। साल के प्रारम्भ में ही एफआईजी ने नहीं चलने के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर अपने ही नए रिकॉर्ड कायम करें, किसानों को खूब ललचाया। लेकिन पोर्टल ने सर्वर समस्या का मोह नहीं छोड़ा। इतने में सहकारिता विभाग ने कंप्यूटराइजेशन की आड़ में लंबी छलांग मारकर, ग्राम सेवा सहकारी समितियां में संविदा कर्मियों की नियुक्ति का फरमान जारी कर दिया। तभी हनुमानगढ़ सीसीबी के चीफ मैनेजर संजय शर्मा को एसीबी ने 8.50 लाख रुपए की संदिग्ध राशि के साथ पकड़ लिया। यह मामला उजागर होते ही सहकारिता विभाग ने प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार मीणा को ही निलंबित कर दिया। एक ओर प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंक पूरे साल योग्य प्रबंध निदेशक के लिए तरसते रहे, लेकिन 'फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया' का हरदम राग अलापने वाले हुनरमंदों ने पुराने ढर्रे से ही प्रबंध निदेशकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों की कमान थमाए रखी। एक कहावत हैं ना कि 'चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता' वह यहां सिद्ध होती नजर आई। उधर, भारतीय रिजर्व बैंक का एक परिपत्र केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए नई झंझट लेकर आ गया। वर्षो पहले हुई कर्ज माफी की बकाया ब्याज राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के ही गले पड़ गई। इस स्थिती को लेकर चिंतत सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा एवं सहकारी बैंकों के वरिष्ठ कार्मिकों की पैरवी ने काम तो जरूर किया। लेकिन उनकी भागदौड़ के बाद भी केवल 200 करोड़ की राशि सहकारी बैंकों के अपेक्स बैंक में संधारित पीडी खाते तक ही पहुंचकर अटक गई और बकाया राशि का प्रावधान सहकारी बैंकों को करना पड़ा। इससे इनकी आर्थिक सेहत खराब होकर रह गई। दूसरी ओर सरकार के कान पर बकाया राशि को लेकर जूँ तक नहीं रेंगी। नवीन कॉ-ऑपरेटिव कोड लाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले में स्क्रीनिंग के दस्तावेज खंगालने के लिए एसीबी की टीम भी बैंक पहुंची। तो कुएं में लटके बंदर की तरह हुई इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग से मांगी। जबकि नवाचारों की श्रेणी में आठ जिलों में नए उपभोक्ता होलसेल भंडार बनाने की स्वीकृति जारी की गई। साथ ही इस वर्ष अन्न भंडारण योजना में 500 एमटी, 250 एमटी एवं 100 एमटी सहित जीर्ण-शीर्ण गोदामों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया। जिससे प्रदेश की भंडारण क्षमता भी 10 लाख के पार पहुंच गई। दूसरी तरफ ऑडिट में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पैनल से हटाया गया। वही वर्षो पहले मृतप्रायः बनी पीएलडीबी में नई जान फूंकने के लिए ओटीएस योजना को लाया गया। वही आयोजनों की श्रेणी में इस साल 'सहकार सदस्यता अभियान', 'सहकार सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव', '72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह', स्पैक्ट्रम और बाड़मेर सीसीबी के संयुक्त तत्वावधान '24वीं राज्य स्तरीय को-ऑप स्पोर्ट्स' प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

जयपुर में सहकार मसाला मेला आयोजन के बाद संभाग स्तरीय मेलों का भी आयोजन हुआ। इसी ही साल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भूटानी ने 'सहकार से समृद्धि' की राज्य स्तरीय बैठक लेकर विभाग की पीठ थपथपाई। तो दूसरी तरफ दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नाबार्ड ने प्रदेश की जैसलमेर, भरतपुर और पाली में आरबीआई के निर्देश पर गार्जियन ऑफिसर नियुक्त किया। इससे केंद्रीय सहकारी बैंकों की खोखली नींव और रेवड़ी कल्चर की परते स्वतः ही खुलती नजर आई।

अमित शाह के आगमन पर जयपुर के दादिया में आयोजित विशाल सहकार एवं रोजगार उत्सव @17.07.2025

देश में राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का अनावरण हुआ। दूसरी ओर देश को पहला सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' के रुप में गुजरात के आणंद में मिला। इस ही साल विश्व की शीर्ष दस सहकारी संस्थाओं में इफको और अमूल ने भी प्रथम दो स्थान हासिल किए।

क्यूआर, गोपाल क्रेडिट और एसी कांड...

सालभर में सहकारिता गलियारों में कई चर्चाएं हुई लेकिन इनमें से भी 22 गोदाम सर्किल पर लगे होर्डिंग पोस्टर और एससी कांड सबसे ज्यादा सुर्खिया बंटारने वाले विषय रहें। साल के अंत तक पहुंचते-पहुंचते जोधपुर के राजीव गांधी सहकार भवन में बड़े-बड़े धमाके के साथ प्लास्टर गिराता हुआ नजर आया। तो समर्थन मूल्य खरीद पर फर्जी पंजीयन का पर्दाफाश होने पर बयोमैट्रिक पहचान के जरिए खरीद का बयान सहकारिता मंत्री ने दिया। इस वर्ष में सहकारी समितियां ने मिलेट्स आउटलेट्स की स्थापना में बड़ी रुचि दिखाई। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने क्यूआर कोड़ की सुविधा भी प्रारम्भ की। जबकि बाड़मेर सीसीबी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अरोपो से घिरी रही। यहां स्वयं सहकारिता विभाग पंजीयक ने जांच करवाई और प्रबंध निदेशक वासूदेव पालीवाल को निलंबित किया। इसकी लपटें अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक तक कारण बताओं नोटिस के रूप में जरूर पहुंची। हालांकि राजधानी में पद का दुरूपयोग करने, संस्था को आर्थिक हानि पहुंचाने तथा विभाग की छवि धूमिल करने से संबंधित अधिरोपित आरोपों के क्रम में कार्मिक विभाग ने सहकारिता सेवा के अधिकारी संजय पाठक, संदीप खण्डेलवाल, जितेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्रसिंह (सेवानिवृत्त)को 16सीसीए चार्जसीट थमा दी।

भर्ती, कैडर अथोरिटी और रिस्क रिलीफ फंड...

इस साल सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित करने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी जयपुर के दादिया में आएं। इस ही साल 'सहकारिता का सफरः अतीत से वर्तमान तक' विषय पर नेहरू सहकार भवन में प्रदर्शनी भी लगी। तो किसानों को महंगी बीमा प्रीमियम दर से बचाने के लिए सरकार ने रिस्क रिलीप फंड भी बनाया। एक ओर सहकार सदस्यता अभियान का आयोजन कर 8.50 नए सदस्य बनाए। तो दूसरी ओर पैक्स व्यवस्थापकों ने राजस्थान सहकारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर, अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार का बिगुल बजा दिया। जिसकी सुध लेकर विभाग ने पिछले तीन दशक से चल रही कैडर अथॉरिटी की मांग पर कमेटी का गठन किया। वही राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड ने सालों बाद सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक में बैंकिंग सहायक एवं प्रबंधक पदों के अलावा राजफैड में विभिन्न पदों पर भर्ती करवाई। हालांकि इस भर्ती में चार बैंकिंग सहायकों को निलंबित करवाने की अनुशंसा भी इस ही राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने की। जबकि बैंकिंग सहायकों के 20 फीसदी पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित भी रखे गए है।

उर्वरक, सोसायटी और शुद्ध लाभ

इस साल उर्वरक की डिमांड के मुकाबले सहकारी क्षेत्र में आपूर्ति कम ही नजर आई। इन सहकारी समितियां को 20 फीसदी ही यूरिया का आंवटन हुआ। तो एक मीडिया रिपोर्ट में, सहकारिता विभाग द्वारा 300 करोड़ का लोन लेकर सहकारी क्षेत्र में उर्वरक खरीद का प्रकरण भी उजागर किया गया। दूसरी तरफ सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियां के गठन में नियमों बड़ा फेरबदल कर, ब्याज मुक्त योजना की अधिकतम ऋण राशि के बराबर हिस्सा राशि कर, समितियों का गठन करने में एक नया रिकार्ड भी कायम किया है। जबकि जनवरी से व्यवस्थापकों के रिक्त पदों की सूचना मांगने की ढुलमुल नीति दिसंबर तक प्रस्ताव अभ्यर्थना तक पहुंची। इसी ही साल कॉनफेड ने 26 करोड़ का शुद्ध लाभ तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने 78.22 करोड़ का लाभ कमाया।

पैक्स-लैम्पस में नवाचार के सफलता की यात्रा

आज का यह विशेष पृष्ठ सहकारी आंदोलन में पिछले साल हुई विभिन्न कार्यकलापों को समर्पित है। बीते साल में सहकारी आंदोलन में हमने खबरों की उस धारा को आगे बढ़ाया है, जो सहकारी संस्थाओं की नब्ज को पहचानते हुए पाठकों तक पहुंचती है। आज प्रस्तुत यह विशेष कोलाज उन चुनिंदा पैक्स-लैम्पस की सफलता की कहानियां एवं नवाचारों की खबरों व लेखों का संग्रह है, जिन्होंने न सिर्फ सहकारी आंदोलन में अपनी नई पहचान बनाई, बल्कि अन्य सहकारी संस्थाओं को भी नवाचार और व्यवसाय विविधिकरण का नया दृष्टिकोण देकर सहकारी आंदोलन को एक अलग दिशा प्रदान की है। यह कोलाज हमारे पिछले वर्षो की मेहनत, संघर्ष और पत्रकारिता के प्रति समर्पण की झलक है। यह एक ऐसी यात्रा है, जो खबरों से होती हुई सीधे पाठकों के दिल तक पहुंची है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) गुरुवार, 1 जनवरी 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सहकारी समितियां के गोदामों की भंडारण क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा गोदामों का निर्माण करवाया जाता रहा है । वर्तमान में राज्य की 6812 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में 9064 गोदाम हैं । जिनकी भंडारण क्षमता 8 लाख 57 हजार 173 एमटी है । जबकि 233 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां में 752 गोदाम बने हुए हैं । जिनकी भंडारण क्षमता 2 लाख 6 हजार 502 एमटी है । इस प्रकार प्रदेश में कुल 9816 गोदामों की भंडारण क्षमता 10 लाख 63 हजार 675 एमटी है । यह जानकारी सहकारिता विभाग द्वारा विधायक रामकेश के सवाल पर दी गई है । दरअसल, गंगापुर विधायक रामकेश ने विधानसभा के तृतीय सत्र में तारांकित प्रश्न किया । इसका जवाब सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया है । जिसके मुताबिक सहकारी समितियां के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि होने एवं सीसीबी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव के आधार बजट को ध्यान में रखकर गोदाम स्वीकृत किया जाता है । हालांकि विधायक ने प्रदेश में पीडीएस का करोबार करने वाली सहकारी समितियां की जानकारी भी सदन के माध्यम से मांगी । तो विभाग ने लिखित जवाब पेश कर बताया कि उचित मूल्य दुकान आंवटन में प्रथम वरियता पैक्स-लैम्पस को दी जाती है । विभाग के अनुसार, वर्तमान में 22 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां द्वारा पीडीएस परिवहन और 1469 ग्राम सेवा सहकारी समितियां द्वारा पीडीएस वितरण का कार्य किया जा रहा है ।

सात खंडों में पैक्स की भंडारण क्षमता

विधानसभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उदयपुर खंड के 1075 पैक्स में 1556 गोदामों का निर्माण करवाया गया । जिनकी भंडारण क्षमता 14686 एमटी है । इसी तरह, कोटा खंड की 636 पैक्स के 873 गोदामों की भंडारण क्षमता 93450 एमटी, भरतपुर खंड की 788 पैक्स के 886 गोदामों की भंडारण क्षमता 78540 एमटी तथा जोधपुर खंड की 1216 पैक्स के 1705 गोदामों की भंडारण क्षमता 138762 एवं बीकानेर खंड की 962 पैक्स के 1353 गोदामों की भंडारण क्षमता 143740 एमटी, इसी प्रकार जयपुर खंड की 1091 पैक्स के 1188 गोदामों की भंडारण क्षमता 119800 एमटी, अजमेर खंड की 1044 पैक्स के 1503 गोदामों की भंडारण क्षमता 136795 है । इस हिसाब से राज्य की 6812 पैक्स के 9064 गोदामों की भंडारण क्षमता 857173 एमटी है ।

केवीएसएस की भंडारण क्षमता

विधानसभा में सहकारिता विभाग के जरिए प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उदयपुर खंड की 29 केवीएसएस के 115 गोदामों की भंडारण क्षमता 32155 एमटी है । इसी तरह, कोटा खंड की 22 केवीएसएस के 104 गोदामों की भंडारण क्षमता 31160 एमटी, भरतपुर खंड की 32 केवीएसएस के 91 गोदामों के 22700 एमटी, जोधपुर खंड की 36 केवीएसएस के 119 गोदामों की भंडारण क्षमता 27670 एमटी, बीकानेर खंड 42 केवीएसएस 125 गोदामों के 39800 एमटी, जयपुर खंड की 32 केवीएसएस के 89 गोदामों की भंडारण क्षमता 21830 एमटी, अजमेर खंड की 40 केवीएसएस 109 गोदामों की भंडारण क्षमता 31187 एमटी है । इस हिसाब से राज्य के 233 केवीएसएस 752 गोदामों की भंडारण क्षमता 206502 एमटी है ।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
पावटा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पावटा

नरेद्रसिंह बालोत
अध्यक्ष

भागीरथसिंह
व्यवस्थापक

विक्रमसिंह बालोत
उपाध्यक्ष
पूर्णत: कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
मोकलसर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मोकलसर

गोविन्द चौधरी
व्यवस्थापक

आईदानराम चौधरी
सहा. व्यवस्थापक
छेलसिंह बालावत
अध्यक्ष
भगवानाराम
उपाध्यक्ष
पूर्णत: कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
उम्मेदाबाद बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. उम्मेदाबाद

मधुसूदन शर्मा
व्यवस्थापक

छतराराम मेघवाल
सहा. व्यवस्थापक
नगेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
पूर्णत: कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सीसीबी की शाखा में दो कार्य. ऋण पर्यवेक्षक लगाए

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक की सायला शाखा के अंतर्गत 19 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 1 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति में ऋण वितरण, फसल बीमा सहित इनके द्वारा होने वाले कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के लिए दो कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक लगाए गए है । इसके लिए जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक नारायणसिंह ने सायला शाखा प्रबंधक की अनुशंषा के आधार पर आदेश जारी किया है । जिसके मुताबिक सायला ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक हरतिंगाराम एवं रेवतड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सुरेश कुमार को अग्रिम आदेशों तक सायला शाखा में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का कार्यभार आवंटित किया गया है । साथ ही, शाखा सायला की 20 सहकारी समितियां आवंटित कर ऋण पर्यवेक्षक पद का समस्त बैंकिंग कार्य संपादित करने के लिए निर्देशित भी किया है । जबकि सीसीबी की ओर से जारी आदेशानुसार, कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक हरतिंगाराम को बाकरा, बैरठ, रेवतडा, थलवाड, वालेरा, चौराउ, तुरा, आसाणा, ओटवाला, वीराणा महिला सहकारी समिति आवंटित की गई है । इसी तरह, कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक सुरेश कुमार को सायला, आलासन, केशवना, उम्मेदाबाद, ऐलाना, माण्डवला, बालवाडा, बिशनगढ नरसाणा, आंवलोज सहकारी समिति आवंटित की गई है ।

वर्ष 2024-2025 में 1137.42 लाख का कारोबार किया और समिति का किसानों को वितरित किया लाभांश

बिलाड़ा सहकारी समिति का वार्षिक अधिवेशन संपन्न, 12.21 लाख का शुद्ध लाभ किया अर्जित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले के बिलाड़ा में स्थित वृहद बहुधंधी सहकारी समिति बिलाड़ा का 65वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन विधायक अर्जुनलाल गर्ग के मुख्य आतिथ्य एवं समिति अध्यक्ष लक्ष्मण लखावत की अध्यक्षता में किया गया । इसमें सर्वप्रथम समिति व्यवस्थापक पूनाराम काग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखे प्रस्तुत कर, बताया कि इस वर्ष में समिति ने 1137.42 लाख रुपए का कारोबार किया और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12.21 लाख रुपए का शुद्ध लाभ भी अर्जित किया। इस वर्ष की व्यापार कार्य की प्रगति को बहुत अच्छी है । उन्होने बताया कि 58.37 लाख रुपए के कुल लाभ में से 46.16 लाख रुपए कोष के रूप में बनाए जाने के बाद शुद्ध लाभ 12.21 लाख रुपए रहा। साथ ही समिति अध्यक्ष लक्ष्मण लखावत ने वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर, अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दिया । उन्होने कहा कि समिति सदस्यों के सुझावों के अनुसार कार्य कर रही है और किसानों को समय-समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराती रही है। बिलाड़ा में यूरिया खाद की कभी कमी नहीं हुई। समिति सदैव किसानों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रयासरत रहेगी। इसके अलावा, अधिवेशन में किसानों को लाभांश का वितरण किया गया । इस दौरान पूर्व मंत्री मिश्रीलाल सिरवी, मदन सिंह, बाबूलाल राठौड़, फुआराम राठौड़, कृषि अधिकारी और बीज उत्पादक मैनेजर सहित समिति के पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

सतत और लाभप्रद कृषि को बढ़ावा दिया जाएं

वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कृषि के आधार को मजबूत किया है। सहकारिता के माध्यम से इसे किसानों की समृद्धि के लिए उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति में कम पानी, कम रासायनिक उपयोग और न्यूनतम जोखिम वाली खेती पर जोर है। इसके तहत वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई प्राकृतिक खेती, मिट्टी परीक्षण और जोखिम कम करने वाली फसलों का चयन शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिट्टी और जल सुरक्षा, संस्थागत ऋण, बाजार पहुंच, उत्पाद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देना आवश्यक है। भविष्य में सब्सिडी पर निर्भर खेती की जगह सतत और लाभप्रद कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट की अनुपालना रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है । इसके लिए इस कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है । जिसके अनुसार, विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । जिसमें पाया गया कि गत कई सालों से जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है । जबकि सहकारिता विभाग पंजीयक के परिपत्रों की पालना में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं 122 (क) के प्रावधानों के तहत पैक्स की ऑडिट संपन्न होने के बाद आमसभा में अनुमोदन के उपरांत 15 दिवस में अनुपालना रिपोर्ट मय अंकेक्षक टिप्पणी विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय को भिजवाई जानी चाहिए । ऐसे में विशेष लेखा परीक्षक ने समस्त पैक्स व्यवस्थापक एवं अध्यक्षों को पत्र जारी कर व्यवस्थापकों को ऑडिट रिपोर्ट मय अंकेक्षक टिप्पणी कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है ।

11 सहकारी समितियों में निर्मित होंगे 100 एमटी के गोदाम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के आठ जिलों की 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 100 एमटी क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक मंजू राजपाल ने हाल ही में स्वीकृति जारी की है । जिसके अनुसार, कोटा जिले की खैराबाद, नौनेरा, चुरू जिले की बालेरा, सीकर जिले की मोटलावास, दौसा जिले की करनावर, देवरी, ढोलावास, सलुम्बर जिले की डींगरी, राजसमंद जिले की रिछेड, बूंदी जिले की काछोला ग्राम सेवा सहकारी समिति के अलावा बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण होगा । गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रत्येक सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
सियाना बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सियाना

प्रदीपसिंह चौहान
अध्यक्ष
पूर्णत: कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
डूंगरसिंह राठौड़ उपाध्यक्ष
नरपतसिंह चौहान व्यवस्थापक
प्रकाशसिंह राव सहा. व्यवस्थापक
गंगाराम सरगरा सहा. कर्मचारी

बाड़मेर में सहकार भारती की बैठक का हुआ आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में सहकार भारती की एक बैठक का आयोजन सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल के मुख्य आतिथ्य एवं सहकार भारती के अध्यक्ष अक्षयदान चारण की अध्यक्षता में किया गया । इस बैठक में संगठन के विस्तार एवं सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया । साथ ही, बाड़मेर जिले में सहकार भारती के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और राज्य एवं केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम किसान तक पहुँचाने पर चर्चा की गई । जिसके बाद, किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाले फसली ऋण और गोपालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई । तथा किसानों को अपनी छोटी-छोटी बचत को समितियों में जमा करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके अलावा बैठक में ग्राम स्तर पर कार्यरत सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात रखी गई। इस दौरान समिति सचिव मनोहर सिंह चारण, कोषाध्यक्ष हरीश सोलंकी, आशु लाल सोनी, और चेतन सोनी छोगालाल सोनी, पूर्व सरपंच (बाड़मेर ग्रामीण) नाथू सिंह, भैराराम जांगिड़ और रमेश, कुलदीप चौधरी, मुकेश परोहित, हिंमाशु पवार आदि मौजूद रहें ।

नवगठित सहकारी समिति के पहले संचालक मंडल का कार्यकाल तीन माह का ही निर्धारित

50 सहकारी समितियों में राजकीय हिस्सा नहीं होने के कारण नहीं हो सकती प्रशासक की नियुक्ति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के बीकानेर जिले में वर्ष 2019 से 2024 के बीच 50 नवगठित बहउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों में राजकीय हिस्सा नहीं होने के कारण प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा सकता हैं । इसके चलते इन समितियों में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत मनोनीत अस्थाई संचालक मण्डल अब तक कार्यरत है । ऐसा सहकारिता विभाग द्वारा विधानसभा में लिखित जवाब दिया गया है । दरअसल, कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी ने बीकानेर जिले में वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मनोनित अस्थाई संचालक मण्डल को लेकर विधानसभा के चतुर्थ सत्र में तारांकित प्रश्न किया । इसका जवाब सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया है । जिसके मुताबिक, बीकानेर जिले में नवगठित इन 50 पैक्स में आज भी अस्थाई संचालक मण्डल कार्यरत है । जबकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 27(1) के प्रावधानानुसार किसी भी नवगठित सहकारी समिति के प्रथम संचालक मण्डल का कार्यकाल तीन माह निर्धारित है। इस कारण इन 50 समितियों में इन प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है । इसके चलते अब उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 28(11) (1) के तहत अध्यक्षों को निर्योग्य किये जाने सबंधी नोटिस 12 अक्टूबर 20225 को जारी कर, कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

राजकीय हिस्सा नहीं होने से प्रशासक नियुक्ति संभव नहीं

कोलायत विधायक ने इन 50 समितियों में प्रशासक नियुक्ति के लिए भी सवाल अंकित करवाया । तो सहकारिता विभाग ने अपना लिखित प्रतिउत्तर पेश कर, सदन के जरिए बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 45 (5) के तहत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को इन 50 समितियों की निर्वाचन अभ्यर्थना प्राप्त होने पर ही निर्वाचन करवाया जा सकता है । हालांकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30(1) के प्रावधान के मुताबिक इन 50 समितियों में राजकीय हिस्सा राशि नहीं होने के कारण अधिनियम अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया जाना भी संभव नहीं है ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।